

- * **कथन (A):** संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं
- कारण (R):** कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं।
 - (A) और (R) दोनों सत्य हैं, किंतु (R) सही स्पष्टीकरण नहीं है (A) का।
- * सही कथन हैं
 - प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो।
- * भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है — भारत का राष्ट्रपति
- * राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है— 44 वें संशोधन द्वारा
- * राष्ट्रपति लोक सभा को भंग कर सकते हैं
 - केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुज्ञप्ति पर
- * अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है— राष्ट्रपति द्वारा
- * भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथन सही हैं—
 - वह संसद का एक संघटक भाग है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है।
- * भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया, वह था—
 - भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक
- * एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था, जिसे संविधानिक शब्दावली में 'जेबी निषेधाधिकार' कहा जाता है, वह थे
 - ज्ञानी जैल सिंह
- * राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं — अनुच्छेद 111 के अंतर्गत
- * जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है
 - राष्ट्रपति को
- * राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है
 - विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोककर रखना तथा संसद को संदेश भेजना
- * राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है
 - विधेयकों पर स्वीकृति देना
- * जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने (वर्ष 2002 में) चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने उसे अपनी सहमति दी
 - अनुच्छेद 123 के अंतर्गत
- * भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है
 - अनुच्छेद 123 के अंतर्गत
- * राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद रखा जाना आवश्यक है
 - 6 सप्ताह तक
- * भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है
 - वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री
- * राष्ट्रपति नियुक्ति करता है—
 - भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल
- * भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है—
 - प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त
- * संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है
 - अनुच्छेद 160 में
- * भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है
 - राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का
- * राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है
 - अनुच्छेद 143
- * भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है — राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए
- * संविधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति की 'शक्ति' नहीं है
 - संसद के सदनों को संदेश भेजना
- * भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, कि वह
 - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए
- * राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक
 - न्यायिक शक्ति है
- * भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त प्राधिकार हैं
 - औपचारिक (स्टिट्यूलर) और विधिक, संवैधानिक और नाममात्र
- * भारतीय संविधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे संसद के पटल पर रखवाएँ
 - संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को
- * वह संवैधानिक विशेषाधिकार, जो राष्ट्रपति का नहीं है
 - वितीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना
- * संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है
 - केंद्रीय मंत्रिमंडल
- * **कथन (A):** भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से निम्न है।
- कारण (R):** भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है
 - A सही है, परंतु R गलत है।

- * कथन (A) : राष्ट्रपति संसद का भाग है।
कारण (R) : संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है।
- (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
- * कथन (A) : रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है।
कारण (R) : प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं।
- (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
- * स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे — बिहार से
- * भारत के चौथे राष्ट्रपति — श्री बी.वी. गिरि थे
- * दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे — डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- * भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है — नीलम संजीव रेड्डी
- * सूची-I का सूची-II से सुमेलन निम्नवत है-

सूची-I (राष्ट्रपति)	सूची-II (अवधि)
फखरुद्दीन अली अहमद	1974-1977
एन. संजीवा रेड्डी	1977-1982
डॉ. ज़ाकिर हुसैन	1967-1969
बी.वी. गिरि	1969-1974
- * राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे — नीलम संजीव रेड्डी
- * भारत के राष्ट्रपतियों में 'दार्शनिक-राजा' अथवा 'दार्शनिक-शासक' के रूप में जाना जाता है — डॉ. राधाकृष्णन
- * भारत के राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है — बी.वी. गिरि
- * भारत के राष्ट्रपति को 'मिसाइल मैन' की संज्ञा दी जाती है — डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को
- * भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, वह — जस्टिस एम. हिदायतुल्ला
- * कथन सत्य है-
— राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम-से-कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सभापति बनता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे
- * कथन : अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
कारण : राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है।
- कथन सही है, परंतु कारण गलत है।
- * श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम था — 12वां
- * एक विधेयक, जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और बाद में अधिनियम बन जाता है — जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है

- * किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है — राष्ट्रपति को
- * "वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है" यह उक्ति लागू होती है — राष्ट्रपति
- * भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में बिहार का राज्यपाल रह चुका था — डॉ. ज़ाकिर हुसैन (वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी)
- * राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था — एडविन ल्यूटियनस द्वारा

उपराष्ट्रपति

- * भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचकगण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं — संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य
- * कथन (A) : कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा, जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है।
कारण (R) : उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपर्युक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर सही है — दोनों (A) और (R) सत्य हैं तथा (R), (A) का एक नान्य स्पष्टीकरण है।
- * उपराष्ट्रपति से संबंधित सही कथन हैं — किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का।
- * भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है — लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से
- * भारत का उपराष्ट्रपति
 1. भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है।
 2. के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य (दायित्व) नहीं है।
 3. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है।
 4. राष्ट्रपति की पद-त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
- * उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है — राज्य परिषद (राज्य सभा) के प्रस्ताव के द्वारा
- * उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है — राज्यसभा में
- * राज्यसभा का सभापति है — उपराष्ट्रपति
- * एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है, जो उसका सदस्य नहीं होता है — राज्यसभा
- * दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे — डॉ. एस. राधाकृष्णन और बी.वी. गिरि
- * मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक — 12वां

केंद्रीय मंत्रिपरिषद

- * भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही है
 - प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है।
- * भारत का प्रधानमंत्री _____ होता है। — निम्न
- * सत्य कथन है—
 - (a) राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है।
 - (b) कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता।
 - (c) एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए दो मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी।
- * भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है— — केंद्रीय सरकार का
- * भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का—
 - प्रधानमंत्री के पास
- * कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं — केवल कैबिनेट मंत्री
- * संसदीय शासन में वास्तविक/कार्यपालिका शक्ति होती है
 - प्रधानमंत्री के पास
- * सही कथन है
 - राष्ट्रपति, भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आबंटन के लिए नियम बनाएगा।
- * यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो
 - वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे
- * भारतीय संविधान का प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है
 - अनुच्छेद 75
- * आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है — लोक सभा का सदस्य
- * "कौन्सिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च" का अध्यक्ष है
 - भारत का प्रधानमंत्री
- * राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है — प्रधानमंत्री
- * भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय
 - जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे छः माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए।
- * भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए
 - 25 वर्ष
- * उपप्रधानमंत्री पद का सृजन
 - संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ।
- * प्रधानमंत्री को — राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है
- * भारत का प्रधानमंत्री—
 - अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है
- * जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है—
 - छह माह तक
- * भारत की संसद के संबंध में कथन सही है
 - संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, संसद का सर्वप्रमुख कार्य है, मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए
- * मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है
 - 1. लोकसभा के प्रति
 - 2. एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत
 - 3. अनुच्छेद 75(3) के अनुसार
- * केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत सही स्थिति है
 - राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक, उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। अपरस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी।
- * सही कथन हैं
 - संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे। विधि-निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को सूचित करेंगे।
- * भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है
 - प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे, तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए
- * भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है
 - विश्वास प्रस्ताव
- * बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा
 - लोकसभा के सदस्यों द्वारा
- * अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है
 - स्पीकर की
- * लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध 'अविश्वास' का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है
 - 50
- * भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही कथन है—
 - 1. भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है।
 - 2. अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुरःस्थापित किया जा सकता है।
- * लाभ के पद का निर्णय (Decision) करेगा
 - संघीय संसद

- * भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका.....के अधीन रहकर कार्य करती है। — विधायिका
- * उत्तर प्रदेश का नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना ? — चैत्राश नाथ काटजू
- * स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे — स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के.पणमुखम चेटी थे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर, 1947 को प्रस्तुत किया था। 1949 में उनके स्थान पर जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था।
- * भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री था — बी.आर. अम्बेडकर
- * भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है — बजट शब्द
- * भारत के 12 वें प्रधानमंत्री थे — देवेगौड़ा
- * सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है—
(i) विश्वनाथ प्रताप सिंह — 2 दिसंबर, 1989-10 नवंबर, 1990
(ii) चंद्रशेखर - 10 नवंबर, 1990 - 21 जून, 1991
(iii) एच.डी देवेगौड़ा - 1 जून, 1996- 21 अप्रैल, 1997
(iv) इंदर कुमार गुजराल-21 अप्रैल, 1997-18 मार्च, 1998
(v) अटल बिहारी वाजपेयी— 19 मार्च, 1998-22 मई, 2004
नोट- उल्लेखनीय है कि अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल इस प्रकार है— 16 मई, 1996 से 1 जून, 1996 तक, 19 मार्च, 1998 से 26 अप्रैल, 1999 तक तथा 13 अक्टूबर, 1999 से 22 मई 2004 तक।
- * एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं—
— जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह
- * भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई — लाल बहादुर शास्त्री की
- * भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे — चंद्रशेखर
- * भारत के प्रधानमंत्रियों में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ — चौधरी चरण सिंह
- * संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह— — अनुच्छेद 352 में
- * भारत के केंद्रीय मंत्री रहे हैं—
1. वी. पी. सिंह 2. आर. वेंकटरमण
3. वाई. बी. चव्हाण 4. प्रणब मुखर्जी
- * उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, प्रधानमंत्री — नरसिम्हा राव द्वारा
- * मनमोहन सिंह के संबंध में सही कथन है—
— भारत के पूर्व वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि
- * कथन : (1) मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं।
कारण : (2) संसदीय प्रणाली में 'मंत्रियों का उत्तरदायित्व' का सिद्धांत कार्य करता है।
— कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- * कथन (A) : भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के प्रति उत्तरदायी है।
कारण (R) : लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं।
— कथन गलत है, पर कारण सही है।
- * कथन (A) : किसी व्यक्ति को उपप्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है।
कारण (R) : वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।
— (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- * संविधान संशोधनों में से एक, बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या, प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी — 91वां
- * केंद्रीय सरकार के संदर्भ में सही है
— 15 अगस्त, 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी।
- * अधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है — श्वेत पत्र
- * प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े — अनुच्छेद 257
- * संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधारित था
— गोपालस्वामी आयरंग रिपोर्ट पर
- * मंत्रिमंडल सचिवालय का/के कार्य हैं/हैं
1. मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना
2. मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता
- * सही सुमेलन है—
(a) जे. एल. नेहरू — शांति वन
(b) एल. बी. शास्त्री — विजय घाट
(c) इंदिरा गांधी — शक्ति स्थल
- * 'जय जवान जय किसान' का नारा दिया — लाल बहादुर शास्त्री

महान्यायवादी और सी. ए. जी.

- * भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है
— अटॉर्नी जनरल
- * राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करता है
— भारत का महान्यायवादी
- * भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है — राष्ट्रपति द्वारा
- * भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है
— महान्यायवादी
- * अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्यक्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा
— महान्यायवादी को
- * भारत के महान्यायवादी (Attorney General) के विषय में सही है—
(1) वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है
(2) उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं
- * संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है
— भारत के अटॉर्नी जनरल को
- * भारत का महान्यायवादी
(1) लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है
(2) लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है।
(3) लोकसभा में बोल सकता है
- * सॉलिसिटर जनरल होता है
— कानूनी/न्यायिक सलाहकार
- * कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है?
— एडवोकेट जनरल (महाधिवक्ता)
- * भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है—
— राष्ट्रपति द्वारा
- * भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है
— अनुच्छेद 148 के अंतर्गत
- * भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है
— भारत के राष्ट्रपति को
- * भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था
— संविधान द्वारा
- * भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है
— 6 वर्ष
- * भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही है—
(a) उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
(b) उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है।
(c) सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं।
- * भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन किया जाता है—
(a) भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना
(b) आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना
(c) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखापरीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना
- * लोक निधि के फलोरूपादक और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ-साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय का महत्त्व है—
(i) CAG की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार-विमर्श करती है; (ii) CAG के प्रतिवेदनों से मिली जानकारीयों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं, जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है।
- * नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है—
— संसद की
- * संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है
— भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक
- * नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है
— संसद के दोनों सदनों के संवोधन पर
- * भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है
— लोक लेखा समिति का
- * 1971 का संशोधन (महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति) अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सी.ए.जी. को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया
— 1976 में
- * लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है
— नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को
- * लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रिया-कलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं—
(a) सार्वजनिक खर्च का परीक्षण
(b) सार्वजनिक राजस्व
(c) वित्तीय प्रशासन

वरीयता अनुक्रम

- * अग्रता-क्रम में इनका सही अनुक्रम है-
— भारत में मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य,
मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मंत्रिमंडल सचिव
- * भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आता है — भूतपूर्व राष्ट्रपति
- * भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी है — भारत के मंत्रिमंडल सचिव

संसद (1)

- * लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है - — 25 वर्ष
 - * 84 वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या, 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी, जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है — 2026
 - * भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है — 552
 - * लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी — 31वें संशोधन ने
 - * भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, लोक सभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन.....जनगणना के आधार पर है। — 1971
 - * लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती हैं — जनसंख्या आधार पर
 - * इन राज्यों की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण नहीं है—
— अरुणाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मेघालय
 - * इन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है— — केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक
 - * यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी—
- नोट : अनुच्छेद 330(2) के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, लोक सभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वहीं होगा, जो उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अनुपात
- उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। उदाहरणार्थ, वर्ष 1996 में पश्चिम बंगाल एवं तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लोक सभा सदस्यों की संख्या 42 थी जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें क्रमशः 8 एवं 6 थीं। वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 10 एवं 7 हैं।
 - * लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं — मध्य प्रदेश में
 - * लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति है — भारत के राष्ट्रपति के पास
 - * राज्य विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है — अनुच्छेद 333 के द्वारा
 - * राष्ट्रपति आंग्ल-भारतीय समुदाय से नामित कर सकता है, यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है — 2 सदस्यों को
 - * राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित हैं — 7 वां तथा 31वां संवैधानिक संशोधन
 - * लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है — प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा
 - * लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं — वर्ष में दो बार
 - * लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है — कुल सदस्य संख्या का 1/10
 - * लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, वह है— — 550
 - * लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है — 545
 - * संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है — संसद के दोनों सदनों में
 - * लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है — स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा
 - * लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है— राष्ट्रपति
 - * लोकसभा का कार्यकाल — आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है
 - * लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है — उत्तर प्रदेश
 - * जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व है, लोक सभा में प्रथम स्थान-उत्तर प्रदेश - 80 सीटें
द्वितीय स्थान-महाराष्ट्र - 48 सीटें
तृतीय स्थान- प. बंगाल - 42 सीटें
 - * लोकसभा के स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है — 25

* सही सुनेलित हैं—

राज्य	प्रतिनिधित्व
(i) आंध्र प्रदेश	— 25
(ii) तमिलनाडु	— 39
(iii) महाराष्ट्र	— 48
(iv) छत्तीसगढ़	— 11
(v) पश्चिम बंगाल	— 42

नोट-ज्ञातव्य है कि जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का भाग था, तब वहां कुल सीटों की संख्या 42 थी, किंतु तेलंगाना के पृथक हो जाने पर इनके मध्य सीटों का विभाजन हो गया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 25 तथा तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं।

- * लोकसभा के दो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं — त्रिपुरा से
- * राज्यों/संघशासित क्षेत्र के समूह की लोकसभा में केवल एक सीट है—
— बंझीगढ़, सिक्किम, मिजोरम

- * डिजिटल टैक्शन के बाद यू.पी. में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है — उन्नाव
- * वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा है — 70 लाख रु.
- * लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था — 1952 में
- * नवीं लोकसभा बंग की गई — 13 मार्च, 1991 को
- * भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए— फरवरी, 1998 को
- * कथन (A): रा.ज.न. सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद-विवाद (discussion) पसंद नहीं करती है।

कारण (R): इस नियम में वाद-विवाद के साथ-साथ मतदान का भी प्रावधान है।

— A तथा R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है

- * लोकसभा का नेता है — प्रधानमंत्री
- * लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा (क्षेत्रफल के अनुसार) निर्वाचन-क्षेत्र है — तद्वत्

- * भारत में लोकसभा का (स्पीकर) अध्यक्ष — व्यक्ति किता जाता है

- * लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है—

— लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा

- * लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है — उपाध्यक्ष को
- * लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है

— लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा

- * प्रो-टेम स्पीकर का कर्तव्य होता है — सदस्यों को शपथ दिलाना
- * लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) अपने 'कॉस्टिंग वोट' का प्रयोग केवल करते हैं

— जब वोट बराबर-बराबर होने के नाते 'टाय' (Tie) हो

- * संविधान का एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा — अनुच्छेद 100

- * लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे — जी.वी. मावलंकर
- * प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था— — जी.वी. मावलंकर

- * लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं — गीरा कुमार
- * लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं — एम. थाम्बी दुरई
- * यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों, तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह

— मत-बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं।

- * प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे — पी.ए. संगमा
- * लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से इसकी देखरेख में कार्य करता है — लोकसभा अध्यक्ष

- * लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनु. जाति/अनु. जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः है

— वर्ष 2011 में निर्वाचन आयोग द्वारा अगंभीर प्रत्याशियों की संख्या कम करने हेतु जमानत राशियां बढ़ाई गई हैं, जो इस प्रकार हैं—
लोकसभा चुनाव - सामान्य वर्ग - 25,000 रु.

अनु. जाति/जनजाति वर्ग - 12,500 रु.

राज्य विधान सभा - सामान्य वर्ग - 10,000 रु.

अनु. जाति/जनजाति वर्ग - 5,000 रु.

- * लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है — द्वितीय वाचन में

- * निम्न शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं—

I. धन/वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।

II. धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में।

III. मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में।

संसद (2)

- * राज्य सभा में होते हैं — 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं

- * राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है — उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान के आधार पर

- * राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं— — राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा

- * राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है — 6 वर्ष का

- * राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि—
— इसे विघटित नहीं किया जा सकता है
- * हमारे संविधान के अनुसार, राज्यसभा का कार्यकाल
— समाप्त होने का विषय नहीं है।
- * प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई
— नरगिस दत्त
- * राज्यसभा के संदर्भ में कथन सही है
— इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं
- * राज्यसभा की एकात्मिक शक्ति के अंतर्गत आता है
— नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन
- * राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही है—
(i) राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है।
(ii) राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा।
(iii) ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है।
- * राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिवक शक्ति प्राप्त कर लेती है, यदि इसके लिए एक संकल्प—
— राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित कर लिखा जाए
- * सही कथन हैं—
1. राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है।
2. राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है।
- * वह विशेषाधिकार जो भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं
— संसद को, राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु शक्ति बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना
- * संसद को राज्य सूची के विषय के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है
— अनुच्छेद 249
- * भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही-सही वर्णित करता है
— इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है
- * सही सुमेलित है—
आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें - 18
महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें - 19
कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें - 12
प. बंगाल में राज्यसभा की सीटें - 16
- (तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 तथा तेलंगाना में 7 हैं)

- * राज्यसभा का अध्यक्ष — उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है।
- * राज्य सभा के वर्तमान समापति हैं — बैकैया नायडू
- * राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में सही है—
(1) उम्र कम-से कम 30 वर्ष होना चाहिए
(2) राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए
- * राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या है — 250
- * राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, तो तत्पश्चात होगा
— लोकसभा, राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है
- * राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है
— मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो
- * राज्यसभा के विषय में सही है—
1. यह भंग नहीं की जा सकती है।
3. प्रत्येक दो वर्ष बाद इसके एक-तिहाई सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है।

संसद (3)

- * कथन (A): अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।
कारण (R): संसद, भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है।
— (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
- * एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक होना आवश्यक है
— दो बार
- * संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए—
— छः महीने का
- * भारत के संविधान में कथित है—
(1) राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा
(2) संसद राष्ट्रपति और दो सदनों में मिलकर बनेगी
- * भारतीय संसद बनती है — लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से
- * संसद का अनन्य भाग नहीं है
— उपराष्ट्रपति
- * संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं—
1. अध्यक्ष, लोकसभा
2. उपाध्यक्ष, लोकसभा
3. महासचिव लोकसभा
4. अध्यक्ष, राज्यसभा
- * संसद/विधान सभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है, जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है
— 60 दिन

- * सर्वप्रथम एक सांसद/विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी साठ लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा — **राज्यसभा का**
- * संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों के निर्धारित करता है — **अनुच्छेद 105**
- * किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है, जब वह — **किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है।**
- * लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है — **राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को**
- * सही कथन है — **किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है**
- * संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है
 1. अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु।
 2. संबंधित राज्य की सहमति से।
 3. राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में।
 4. राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे।
- * भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती, जब तक — **राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो।**
- * अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है — **बिना किसी राज्य की सहमति से**
- * संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है — **संसद**
- * धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो, किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, वह क्रियाविधि है — **यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे**
- * सदन का अध्यक्ष, सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है — **बैठ जाना (Yielding the floor)**
- * 'शून्यकाल' संसदीय व्यवस्था की देन है — **भारत की**
- * लोकसभा में 'शून्यकाल' की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है — **एक घंटा**
- * संसद में शून्यकाल का समय है — **दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक**
- * राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है— — **प्रश्न-उत्तर सत्र**
- * अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है— — **अनु. 253 के अंतर्गत**
- * कथन सही है — **धन विधेयक लोकसभा में पुरःस्थापित किया जाता है।**
- * लोकसभा द्वारा पारित धन-विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा, यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती— — **14 दिनों तक**
- * राज्यसभा को 'धन विधेयक' प्राप्त होने के बाद इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए — **14 दिनों के अंदर**
- * जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट (रेफर) किया जाता है, तो इसे पारित किया जाना होता है — **उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत द्वारा**
- * संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा — **लोकसभा का अध्यक्ष (स्पीकर)**
- * संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है— — **एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो**
- * सही कथन हैं—
 1. भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संसदीकृत है
 2. लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी
 3. भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग (निरसन) बिल को पारित करने के लिए हुई थी
- * भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी— — **दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में**
- * लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है — **साधारण विधि-निर्माण को पारित करने की स्थिति में**
- * कोई कानूनी विधेयक रखा जा सकता है — **दोनों में से संसद के एक पटल पर**
- * कथन सही है — **राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक, जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा।**
- * सही कथन है — **जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है।**

- * भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है
 - भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते
- * भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है
 - भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन
- * भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है
 - भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते
- * भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए अनुमोदन अनिवार्य है
 - भारत की संसद
- * आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं
 - संसदीय स्वीकृति से पूर्व
- * करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है
 - भारत की संचित निधि में
- * संविधान के धन विधेयक को परिभाषित किया गया है
 - अनुच्छेद 110 के अंतर्गत
- * कोई विधेयक 'धन विधेयक' है या नहीं इसका निर्णय करता है
 - लोकसभा अध्यक्ष
- * धन विधेयक के बारे में सही है—
 - लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है, राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता।
- * सही कथन है
 - धन-संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, राज्यसभा किसी धन-विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है
- * वे विषय जिन्हें धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित किया गया है
 - कर से संबंधित उपबंध, उधार (ऋण) लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध
- * कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्बलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे—
 - संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है।
- * बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में सही है—
 - बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है
- * भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आने वाली विधियाँ हैं—
 1. संसद के साम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना
 2. विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना
 3. अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान
 4. संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना
- * संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है
 - आर्थिक कार्य विभाग
- * यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता, तो
 - प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है
- * व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई
 - व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर के
- * आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है
 - आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतीकरण के पूर्व
- * 'लेखानुदान' संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है
 - निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए
- * संसद में 'लेखा के लिए वोट' आवश्यक होता है
 - जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती।
- * लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच अंतर है
 - लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवृत्ति दोनों सम्मिलित होते हैं।
- * व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है
 - अनुदान के अनुरोध के रूप में
- * भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है
 - लोकसभा में
- * सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित हैं—
 1. बजट का प्रस्तुतीकरण
 2. बजट पर चर्चा
 3. विनियोग विधेयक को पारित करना
 4. वित्त विधेयक को पारित करना
- * संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है
 - (1) एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर
 - (2) ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो
 - (3) राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर
 - (4) धन विधेयक पर
- * संदर्भित संबंध संघीय बजट से है
 - कटौती प्रस्ताव
- * पार्लियामेंट द्वारा, 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है
 - 18 वर्ष

- * रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है — संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा
- * भारतीय राजनीति के संदर्भ में, कथन सही है — राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं
- * संसद की एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है — प्राक्कलन समिति
- * प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है — एक वर्ष का
- * सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है — भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक
- * संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है — क्रमशः दो और एक के अनुपात में
- * ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने सीमित किया है — स्थगन प्रस्ताव को
- * तारांकित प्रश्नों के विषय में सही है (i) उत्तर मौखिक दिए जाते हैं (ii) पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं
- * भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है — सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु।
- * संघ सरकार के संदर्भ में सही कथन है — हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है।
- * भारतीय संसद का सचिवालय — सरकार से स्वतंत्र है
- * भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है — न्यायिक समीक्षा से
- * भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था — 13-5-2002 को
- * वह कौन राष्ट्रवादी नेता था, जो 1925 में केंद्रीय विधान सभा का अध्यक्ष (स्पीकर) चुना गया — बिठ्ठल भाई पटेल
- * सही कथन है— — लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- * सही कथन हैं— (1) लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं (2) संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है (3) विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों परिषदों मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है।
- * राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है — अध्यक्ष समिति में
- * सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है — संसद बने
- * लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है — लोकसभा के स्पीकर को
- * संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है — शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंप्यूटोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण
- * लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं — 22 (15 लोक सभा तथा 7 राज्य सभा के)
- * लोक लेखा की संसदीय समिति 1. सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है 2. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है सही सुमेलन इस प्रकार है
- लोक लेखा समिति वित्तीय समिति
राज्य सभा समिति कार्यकारी समिति
स्टॉक बाजार-स्कैम संयुक्त समिति तदर्थ समिति
विभागीय समितियां स्टैंडिंग समिति
- * राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है — इस्टीमेट्स कमेटी से
- * प्राक्कलन समिति गठित की जाती है — लोकसभा के सदस्यों से
- * भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं 1. सार्वजनिक लेखा समिति, 2. प्राक्कलन समिति, 3. सार्वजनिक उपक्रम समिति
- * संसदीय समिति गठित की गई हैं — सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, सरकारी आवासनों के बारे में, आंकड़ों के बारे में
- * 2-जी स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल थे — 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से
- * 2-जी स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष थे — पी.सी. चाको
- * भारतीय संसद प्रशासन (Administration) पर नियंत्रण करती है — संसदीय समितियों के माध्यम से

संसद (4)

- * 'खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम' प्रथम बार लागू हुआ था — 1954 में
- * सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं — संज्ञेय तथा संज्ञेयतः विचारणीय
- * सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किया जाता है — प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा

- * सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है
— संपूर्ण भारत पर
- * सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में उत्तरदायी होता है
— निदेशक, प्रबंधक, सचिव
- * घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ है
— 26 अक्टूबर, 2006 को
- * सामाजिक अधिनियम है
— एंटी डॉवरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्रीवेन्शन ऑफ इमॉरल ट्रेफिक एक्ट
- * भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों/विशेषाधिकारों के संदर्भ में कथन सही है
— (i) उपभोक्ताओं को ख़ास की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। (ii) उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर, उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है।
- * क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम अधिनियमित हुआ था — 1871 में
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 प्रवृत्त हुआ है
— 30 जनवरी, 1990 को
- * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ प्राप्त हैं
— केंद्र सरकार को
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है
— एक वर्ष
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार _____ की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है।
— उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है, जो आधारित है
— संरक्षा विवेक का सिद्धांत पर
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और बसूल करने की शक्ति है
— राज्य सरकार को
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में, न्यायालय उपधारित कर सकता है
— दुष्प्रेरण, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य
- * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की मारवाड़ी दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है
— धारा 6 में
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन पूर्णतः निषिद्ध है
— गिरफ्तारी पूर्व जमानत
- * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है
— धारा 18 में
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो _____ रैंक से कम न हो।
— उप-अधीक्षक
- * वे शक्तियाँ जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को दी गई हैं
— (i) किसी अपराध के दोषसिद्ध अभियुक्त की संपत्ति का समग्रहरण (ii) ऐसे व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना (iii) ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना, जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है।
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन विशेष न्यायालय शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता
— सामूहिक जुर्माना आरोपित करना
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है
— शीघ्र विचारण
- * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम, 1995 की 'जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरी समिति' के गठन का उपबंध किया गया है
— धारा 17 के अंतर्गत
- * सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (PESA) अधिनियम को 1966 में अधिनियमित किया। उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात है
— (i) स्वशासन प्रदान करना (ii) पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना (iii) जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना
- * संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई
— 15 जून, 2005 को
- * सूचना का अधिकार के संबंध में सही है
— वह एक विधिक अधिकार है
- * सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष
— 2005 में
- * सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित है
— नमिता शर्मा बनाम भारत संघ

- * **कथन (A) :** सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है।
- कथन (R) :** इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलें तक यात्रा करनी है।
- (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- * सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है
 - सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पद्धति
- * इस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आर.टी.आई. आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का करण अवश्य बताना चाहिए
 - मद्रास उच्च न्यायालय ने
- * अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्राधिकारी होगा
 - ग्राम सभा
- * राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 भारतीय संविधान के प्रावधान के आनुरूप अधिनियमित हुए थे
 - स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के आनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है।
- * गूमी अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के संदर्भ में कथन सत्य है
 - इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था

सर्वोच्च न्यायालय

- * भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था
 - 28 जनवरी, 1950 को
- * भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है
 - 31
- * भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी
 - भारतीय संविधान के द्वारा
- * सही कथन है—
 - (i) सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। (ii) सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है, जिसमें अपील की जाती है। (iii) सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट-मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय/अदालतों की सुनवाई कर सकता है।
- * भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है
 - संसद में
- * सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, पत्र लिखकर
 - राष्ट्रपति को

- * सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश.....के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं।
 - संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने
- * सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है
 - 65 वर्ष
- * उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है
 - संसद द्वारा
- * भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु प्रावधान हैं
 - (i) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करना पड़ता है। (ii) न्यायाधीशों का वेतन भारत की सचिव निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधान मंडल को अपना मत नहीं देना होता है।
- * सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं
 - किसी भी न्यायालय में नहीं
- * भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है
 - राष्ट्रपति
- * सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा
 - सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ
- * सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ (Adhoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जब
 - न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता
- * भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है
 - सर्वोच्च न्यायालय में
- * सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश, जो इस मंडल के सदस्य होते हैं, की संख्या होती है
 - 4
- * उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए
 - पांच
- * केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है—
 - मूल अधिकारिता के अंतर्गत
- * उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं
 - भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद
- * उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ इस केस में बनी—
 - गोलकनथ केस में
- * उच्चतम न्यायालय ने 'संविधान के मूल ढाँचे' का सिद्धांत प्रतिपादित किया था
 - केशवानंद भारती वाद में

- * उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि "मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं।"
- गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में
- * सही सुमेलित है—
 - इंदिरा साहनी वाद - अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत
 - विशाखा वाद - अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण
 - मेनका गांधी वाद - अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जी नहीं हैं।
- * संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है — अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनु. 132 को पढ़ना
- * संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, इसके—
 - अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
- * सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन है
 - यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है।
- * भारत में सुधारात्मक बाधिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है—
 - अनुच्छेद 142 के अंतर्गत
- * उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है — अनुच्छेद 137
- * न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय
 - राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है
- * न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है
 - भारत और यू.एस.ए. दोनों में
- * न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है
 - अनुच्छेद 122 के अंतर्गत
- * कोई भी संविधान (संशोधन) कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, यदि वह
 - विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है।
- * भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है
 - विधि का शासन
- * संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है
 - सर्वोच्च न्यायालय को
- * भारत के संविधान का अभिरक्षक (Custodian) है
 - भारत का उच्चतम न्यायालय
- * उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार है
 - राष्ट्रपति को
- * उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है — खंड (1), अनुच्छेद 143 के अंतर्गत
- * विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है — संसद को
- * भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है
 - संसद द्वारा विधि बनाकर
- * उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में कथन सही हैं
 - परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर बंधित किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता।
- * भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है — तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है
- * भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का 'अनुलंघनीय मौलिक ढांचा' घोषित किए गए हैं
 - अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227
- * भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है — 32 अनुच्छेद के तहत
- * सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम-से-कम उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए — 10 वर्ष
- * "मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा... भारत की संभ्रमता और अखंडता को बनाए रखूंगा.... अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा.... संविधान और कानून की रक्षा करूंगा।" यह शपथ ली जाती है
 - भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
- * उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं
 - मूल अधिकारों का प्रवर्तन
- * देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार है
 - सर्वोच्च न्यायालय के पास
- * हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है
 - अनुच्छेद 355 को
- * सही कथन है
 - न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका (PIL) के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं।
- * भारत में 'संविधान की मूल संरचना (बुनियादी ढांचा) के सिद्धांत' का स्रोत है
 - न्यायिक व्याख्या

- * भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक "अभिलेख न्यायालय" है। इसका आशय है कि
 - इसके सभी निर्णयों का साक्षात्कार मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता है।
 - * अभिलेख न्यायालय माना जाता है
 - उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को
 - * भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में सही कथन है
 - सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है।
 - * उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है
 - राष्ट्रपति के अनुमोदन से
 - * टी.डी.एस.ए.टी. के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है
 - केवल सुप्रीम कोर्ट में
 - * जनहित याचिका की शुरुआत की गई
 - न्यायिक पहल द्वारा
 - * पी.आई.एल. है—
 - पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन
 - * जनहित याचिका (पी.आई.एल.) प्रस्तुत की जा सकती है
 - उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में
 - * लोकहित वाद (मुकदमे) की संकल्पना का उद्गम देश है
 - यू.एस.ए.
 - * भारत में 'न्यायिक सक्रियता' संबंधित है
 - जनहित याचिका से
 - * सितंबर, 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई वह न्यायालय है—
 - भारत का सर्वोच्च न्यायालय
 - * यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी
 - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा
 - * उच्चतम न्यायालय ने पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक 'पिजराबंद तोता' है
 - कोयला आवंटन घोटाला वाद में
- ## राज्यपाल
- * संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्राक्कानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि—
 - इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था।
 - * राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है—
 1. विधान सभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए।
 2. मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए।
 3. भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए।
 4. विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए।
 - * राज्यपाल, राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है
 - अनुच्छेद 200 के अधीन
 - * राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष/संवैधानिक प्रमुख है
 - राज्यपाल
 - * जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति करता है
 - भारत का राष्ट्रपति
 - * भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन सही हैं—
 - उसकी आयु कम-से-कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।
 - * राज्यपाल के संबंध में सही कथन हैं—
 - राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है।
 - * राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है
 - उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
 - * किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन सत्य है—
 - (a) वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है
 - (b) वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है
 - (c) सामान्यतया वह पांच वर्ष तक पद पर रहता है
 - * सही कथन है
 - भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है
 - * जब एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियां और भत्ते होंगे
 - इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अर्थात् निर्धारित करें।
 - * किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं
 - भारत के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति शासन अधिनियम के तहत रिपोर्ट भेजना। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को, भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना।